No. 2022/HQ/Admin/RTI-1279 **New Delhi: 03.10.2022**

कुमारी भावना
पुत्री श्री सुनील कुमार
निवासी ग्राम जड़ौदा
तहसील सदर मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश-251003
मोबाइल-8434432552

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 09.09.2022, जो CGM/मेरठ के कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.09.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 04 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
011-23454707

पत्रांक–एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / मेरठ / भाग–VIII दिनांक: 28.09.2022

जे.जी.एम. / एडमिन (सीपीआईओ),
डीएफसीसीआईएल, कार्पोरेट ऑफिस,
न्यू दिल्ली।

विशयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आवेदनकर्ता कु0 भावना पुत्री सुनील कुमार, निवासी ग्राम जडौदा, जनपद मुजफ्फरनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2022

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नवत सूचना चाही गयी हैः–

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>चाही गयी सूचना</th><th>उपलब्ध करायी जा रही सूचना</th></tr>
<tr><td>1</td><td>रेलवे कोरीडोर में अधिग्रहित की गयी भूमि खसरा सं0 690 का अधिग्रहण का मुआवजा प्रार्थीया ने प्राप्त कर लिया है, लेकिन प्रार्थीया को भूमि अर्जन पुर्नवास / आदि का पांच लाख पचास हजार रूपये क्यों नहीं दिया गया है, जबकि प्रार्थीया भूमि अर्जन निकाय पारदर्िता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 3(5) के परिभाशित है।</td><td rowspan="2">डीएफसी परियोजना प्रभावित जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जड़ौदा खसरा सं0 690 की कृशक कु0 भावना नाबालिग के पिता श्री सुनील कुमार की मृत्यु दिनांक 20.06.2003 को, रेल संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20ए की अधिसूचना जारी होने से पूर्व हो चुकी थी। सुनील कुमार की मृत्यु के पश्चात कु0 भावना अपने पिता श्री सुनील कुमार की भूमि पर स्वामित्व प्राप्त कर चुकी थी। कु0 भावना नाबालिग की माता एवं संरक्षिका सविता द्वारा श्री अनिल कुमार से पुनः विवाह कर लिया गया था।
इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया जाता है कि पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन की पात्रता सारणी के अनुसार कु0 भावना नाबालिग, श्रीमती सविता एवं श्री अनिल कुमार को एक ही परियोजना प्रभावित परिवार माना जाता है। उक्त परियोजना प्रभावित परिवार के सदस्य श्री अनिल कुमार पुत्र पूरण सिंह को पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन के तहत भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।
अतः आवेदनकर्ता पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना पात्रता सारणी–2015 (संलग्नक) के अनुसार अनुदान की राशि के पात्र नहीं है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रार्थीया को पुर्नवास के पांच लाख पचास हजार रूपया अब तक मांगने पर भी क्यों नहीं दिया गया। समय–सीमा के अन्दर प्रार्थीया को सूचना उपलब्ध करायें।</td></tr>
</table>

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

उप परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
उप जनसूचना अधिकारी, मेरठ।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2009/INFRA/3/1/10 Pt 2 Dated: 23.5.2015

Managing Director,
DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan
Station Building Complex
New Delhi-110001
Fax-23454605, 23454701

Sub: Approval of Entitlement Matrix for DFC project in accordance with new Land Acquisition Act, 2013.

Ref: (i) DFCCIL letter No. HQ/SEMU/Entitlement Matrix/2015 dated 13.4.15
(ii) This office letter of even No. dated 27.3.15

Reference above, please find enclosed Entitlement Matrix for DFC in accordance with the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act - 2013, duly approved by Railway Board. It is requested to take suitable action to disclose the Entitlement Matrix as part of Resettlement Policy Framework.

Encl: As above

(Sandeep Srivastava)
Director Planning (Special)
Room # 143, Rail Bhawan
Telefax: +91-11-23383525
Email: dplgspl@gmail.com

Copy to:

Mr Atul Agarwal, Senior Transport Specialist, International bank for Reconstruction and Development, Country Office, 70, Lodi Estate, New Delhi-110003: For issue of no objection and with a request to take necessary action for up gradation of the Technical Discussions (13.5.15) for EDFC-3 project to "Negotiations for EDFC-3 Project".

(vi) a family residing on any land in the urban areas for preceding three years or more prior to the acquisition of the land or whose primary source of livelihood for three years prior to the acquisition of the land is affected by the acquisition of such land.

Displaced family: A family, who on account of acquisition of land has to be relocated and resettled from the affected area to the resettlement area.

Land:- it includes benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth.

Land owner:- includes any person-

i. whose name is recorded as the owner of the land or building or part thereof, in the records of the authority concerned; or
ii. any person who is granted forest right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 or under any other law for the time being in force; or
iii. who is entitled to be granted Patta rights on the land under any law of the State including assigned lands; or
iv. any person who has been declared as such by an order of the court or Authority.

Encroacher: A person/family, who transgresses into the public land (prior to the cut of date), adjacent to his/her own land or other immovable assets and derives his/her additional source of shelter/livelihood.

Squatter: A person/family that has settled on the public land without permission or has been occupying public building without authority prior to the cut-off date and is depending for his or her shelter or livelihood and has no other source of shelter or livelihood.

Cut-off Date: The Cut-off date for identifying the affected families including land owners, those having tile claims recognized under other state and central laws, and squatters shall be the date of first land acquisition (LA) notification issued under 20A of Railway Amendment Act of 2008 for the Project for which Resettlement Action Plan is proposed to be prepared.